नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 259
दि. 22.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ईरान की दो टूक: परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका से वार्ता से पहले बढ़ा तनाव

तेहरान। ईरान ने एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह परमाणु हथियार बनाने की किसी भी योजना से पूरी तरह इनकार करता है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू होने जा रही है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में एक बार फिर नई हलचल देखी जा रही है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपने बयान में कहा कि उनका देश परमाणु हथियारों के निर्माण के खिलाफ अपनी नीति को पहले ही स्पष्ट कर चुका है और इसे लिखित रूप में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास पर आधारित है और इसका किसी भी प्रकार के सैन्य उपयोग से कोई संबंध नहीं है।

हालांकि, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने यह भी साफ कर दिया कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार ईरान के संप्रभु अधिकारों का हिस्सा है और इस पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाना हर देश का अधिकार है और ईरान इस अधिकार को किसी भी दबाव में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान को अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

इस बीच, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली आगामी वार्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें और चिंताएं दोनों ही बढ़ गई हैं। स्विट्जरलैंड में होने वाली इस बैठक को क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु समझौते के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघाई ने बताया कि इस वार्ता में केवल परमाणु मुद्दा ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से लेबनान की स्थिति और इजराइल से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा होंगे।

ईरान ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह क्षेत्रीय समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ रही है। ईरान का कहना है कि किसी भी वार्ता में इन मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु नीति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

इसी बीच, ईरान ने यह भी दावा किया है कि कतर में उसकी लगभग 6 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति को मुक्त कराने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो इससे देश की आर्थिक स्थिति को काफी राहत मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें नहीं चाहतीं कि यह वार्ता सफल हो, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि ईरान और अमेरिका के बीच कोई सकारात्मक समझौता होता है तो इससे सबसे अधिक असंतोष उन्हीं को होगा। उनका यह बयान क्षेत्रीय राजनीति में जारी गहरे मतभेदों और अविश्वास को दर्शाता है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में कूटनीतिक प्रयासों को पूरी तरह मौका दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके। उन्होंने स्विस विदेश मंत्री के साथ भी इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की।

IAEA की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था, जिसे 60 प्रतिशत तक संवर्धित किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्तर हथियार-ग्रेड संवर्धन के बेहद करीब है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।

वर्तमान परिस्थितियों में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली यह वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर न केवल दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता पर भी दिखाई देगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बातचीत किसी नए समझौते की दिशा में आगे बढ़ पाएगी या फिर तनाव और अधिक गहरा होगा।

कासगंज में ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ग्राम प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। गंजडुण्डवारा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात ने न केवल एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही राजनीतिक रंजिश और गांव में वर्चस्व की लड़ाई का खतरनाक परिणाम थी।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलेश शाक्य पुत्र बलजीत, निवासी बहारपुर, थाना गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज के रूप में हुई है। उसे रविवार को पुलिस टीम ने दबिश के दौरान पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी की भी भूमिका सामने आई है, जो फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी वारदात की जड़ वर्ष 2021 के ग्राम प्रधान चुनाव से जुड़ी है। उस चुनाव के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक वर्चस्व और व्यक्तिगत रंजिश गहराती चली गई। गांव में प्रभाव जमाने और स्थानीय स्तर पर दबदबा बनाए रखने को लेकर दोनों पक्षों में तनाव लगातार बढ़ता रहा। समय के साथ यह रंजिश इतनी तीखी हो गई कि उसने एक मासूम बच्ची को भी अपनी चपेट में ले लिया।

जांच में सामने आया है कि आरोपी कमलेश शाक्य ने अपने सहयोगी अजय के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि दोनों का उद्देश्य पीड़ित परिवार को डराना और दबाव में लाना था, लेकिन यह साजिश बेहद क्रूर रूप ले बैठी। आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से चार वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने मानवता को झकझोर देने वाला रूप ले लिया, क्योंकि इसमें एक ऐसी बच्ची को निशाना बनाया गया जो पूरी तरह निर्दोष और मासूम थी।

घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार सदमे में है और स्थानीय लोग इस जघन्य अपराध को लेकर गहरा आक्रोश जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक रंजिश और व्यक्तिगत दुश्मनी का ऐसा खतरनाक रूप पहले कभी नहीं देखा गया। घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा।

इस मामले ने एक बार फिर ग्रामीण राजनीति में बढ़ती रंजिश और उसके भयावह परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत स्तर की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई किस तरह हिंसा और अपराध का रूप ले सकती है, यह घटना उसका बेहद दुखद उदाहरण बनकर सामने आई है। एक मासूम की हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और लोगों में यह सवाल गहरा कर दिया है कि आखिर राजनीतिक प्रतिशोध की कीमत निर्दोष बच्चों को क्यों चुकानी पड़ती है।

पानी संकट पर पाकिस्तान की धमकी, भारत को दी युद्ध की चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को लेकर बेहद कड़े और विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई जैसे विकल्प पर भी विचार कर सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद गंभीर जल संकट और आंतरिक जल-वितरण विवादों से जूझ रहा है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर पहले से चल रहा तनाव भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

ख्वाजा आसिफ ने एआरवाई न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पानी अब पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है और यदि इसे खतरे में डाला गया तो देश "कड़े कदम" उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, "जिस क्षण हमें लगेगा कि पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और वह खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। निश्चित रूप से।" उनके इस बयान को क्षेत्रीय कूटनीति में बेहद संवेदनशील और उकसाने वाला माना जा रहा है।

पाकिस्तानी मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि यदि भारत सिंधु जल प्रणाली को प्रभावित करने की दिशा में "तेजी से और खतरनाक तरीके" से आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने दावा किया कि पानी को लेकर किसी भी तरह की बाधा को देश अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा।

यह टिप्पणी भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के जल प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित करने की दिशा में भारत काम कर सकता है। भारत की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि सिंधु जल संधि को तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता।

गौरतलब है कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। इस समझौते के अनुसार सिंधु बेसिन का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता रहा है, जिस पर उसकी कृषि और पीने के पानी की बड़ी निर्भरता है।

इसी बीच पाकिस्तान के अंदर ही पानी को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। देश के कई हिस्सों, खासकर सिंध और बलूचिस्तान में जल संकट गहराता जा रहा है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई प्रमुख नहरों में सामान्य से 40 से 80 प्रतिशत तक पानी की कमी दर्ज की गई है, जिससे खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है।

रिपोर्टों के मुताबिक निचले इलाकों में पानी की कमी के कारण स्थानीय प्रशासन और प्रांतों के बीच भी तनाव बढ़ गया है। सिंध के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ऊपरी क्षेत्र पंजाब द्वारा तय सीमा से अधिक पानी लिया जा रहा है, जिससे निचले क्षेत्रों में गंभीर संकट पैदा हो गया है। यह विवाद अब राजनीतिक रूप भी ले रहा है और सरकार के लिए आंतरिक चुनौती बनता जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा चेतावनी अधिकतर घरेलू दबाव और जल संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच जल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का कारण मानी जा रही है।

सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी मार्ग कोलकाता में इतिहास, राजनीति और स्मृतियों की नई बहस

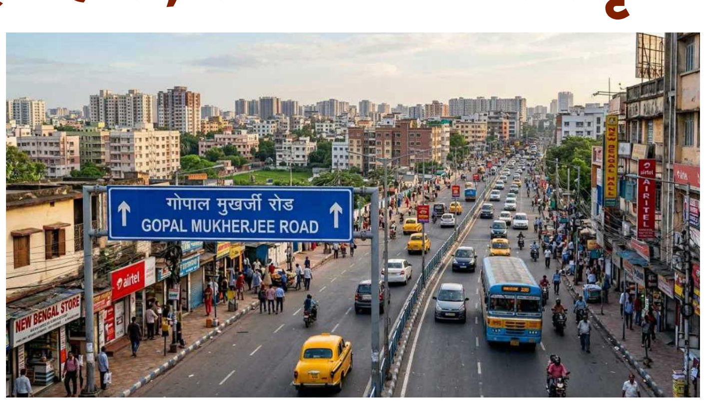

कोलकाता में एक बार फिर इतिहास, राजनीति और स्मृतियों का टकराव देखने को मिल रहा है, जहां नगर निगम द्वारा पार्क सर्कस क्षेत्र स्थित सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी मार्ग किए जाने के फैसले ने पूरे राज्य में नई बहस छेड़ दी है। यह निर्णय भले ही प्रशासनिक रूप से एक सामान्य नाम परिवर्तन जैसा प्रतीत हो, लेकिन इसके पीछे छिपा ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक संकेत इसे एक संवेदनशील मुद्दा बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे "ऐतिहासिक भूल सुधार" बताया है, जबकि दूसरी ओर कई सामाजिक और राजनीतिक वर्ग इसे इतिहास के एकतरफा पुनर्लेखन के रूप में देख रहे हैं। इसी विवाद के बीच गोपाल 'पाठा' एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिनका नाम 1946 के कोलकाता दंगों के संदर्भ में गहराई से जुड़ा माना जाता है। गोपाल मुखर्जी, जिन्हें आमतौर पर गोपाल 'पाठा' के नाम से जाना जाता था, का जन्म कोलकाता के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जीवन किसी बड़े राजनीतिक या सैन्य परिवार से नहीं जुड़ा था, बल्कि वे सामान्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति थे। कॉलेज स्ट्रीट क्षेत्र में उनकी मटन की दुकान थी और यहीं से उन्हें 'पाठा' उपनाम मिला, क्योंकि बंगाली में 'पाठा' का अर्थ बकरा होता है। समय के साथ यह नाम उनकी पहचान बन गया और आम जनता के बीच वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन उनकी ऐतिहासिक पहचान तब बनी जब 1946 में बंगाल में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसे इतिहास में 'ग्रेट कलकत्ता हत्याकांड' के रूप में जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' के बाद कोलकाता में जो हिंसा फैली, उसने पूरे शहर को कई दिनों तक भय, आगजनी और नरसंहार की स्थिति में डाल दिया था। उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी थे, जिनके नाम पर बाद में शहर में कई स्थानों और सड़कों का नामकरण हुआ। उसी ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ी सुहरावर्दी एवेन्यू अब गोपाल मुखर्जी मार्ग के नाम से जानी जाएगी। उस दौर में जब शहर की कानून-व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी, स्थानीय स्तर पर कई समूह अपने-अपने समुदायों की रक्षा के लिए संगठित हो रहे थे, और इसी पृष्ठभूमि में गोपाल पाठा का नाम सामने आया। ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय कथाओं के अनुसार, गोपाल मुखर्जी ने उस समय कुछ युवाओं को संगठित कर एक प्रतिरोधी समूह बनाया था, जिसका उद्देश्य अपने इलाके के लोगों की सुरक्षा करना था। उनके समर्थकों का कहना है कि उस हिंसक दौर में उन्होंने कई हिंदू परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की और कई इलाकों में लोगों को हमलों से बचाने के प्रयास किए। इसी कारण उन्हें कुछ वर्गों द्वारा एक स्थानीय रक्षक के रूप में देखा जाता है। हालांकि, उनके आलोचकों का कहना है कि उस समय की घटनाएं बेहद जटिल थीं और किसी भी व्यक्ति की भूमिका को केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिंसा व्यापक स्तर पर फैली हुई थी और कई समुदायों के बीच तनाव चरम पर था। इतिहासकारों के बीच भी गोपाल पाठा की भूमिका को लेकर मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें उस दौर में आत्मरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि 1946 के दंगों को किसी एक व्यक्ति की भूमिका में सीमित करना ऐतिहासिक तथ्यों का सरलीकरण होगा। उनका कहना है कि उस समय की स्थिति इतनी जटिल और दर्दनाक थी कि उसमें अनेक समूहों और व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं, जिन्हें एकल दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। इस पूरे विवाद के बीच कोलकाता नगर निगम का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी मार्ग किए जाने को कुछ लोग सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय नायकों को सम्मान देने की प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि यह निर्णय इतिहास को नए राजनीतिक दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नाम बदलने के ऐसे फैसले पहले भी कई बार विवाद का कारण बन चुके हैं, और इस बार भी यह मुद्दा केवल एक सड़क के नाम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ऐतिहासिक स्मृति और राजनीतिक विचारधारा के टकराव का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस निर्णय को लेकर बहस तेज हो गई है। एक वर्ग का मानना है कि जिन व्यक्तियों ने कठिन समय में अपने समुदाय की रक्षा की, उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग यह सवाल उठा रहा है कि क्या इतिहास के नाम पर किए जाने वाले ऐसे बदलाव सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकते हैं। इसी बीच कुछ सांस्कृतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात की भी बहस है कि समाज अपने इतिहास को किस दृष्टि से देखता और याद करता है। फिलहाल नगर निगम के इस फैसले के बाद सुहरावर्दी एवेन्यू का नया नाम गोपाल मुखर्जी मार्ग आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाएगा, लेकिन इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता में इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आज भी सड़कों, नामों और स्मृतियों के माध्यम से जीवित राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना हुआ है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बीमारी से बड़ी चुनौती, असुरक्षित दवाओं का खतरा

दवा किसी भी आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह डॉक्टर और दवा दोनों पर भरोसा करता है। मरीज यह मानकर दवा का सेवन करता है कि उसे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद मंजूरी मिली होगी और वह उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन जब सरकार स्वयं यह स्वीकार करे कि बाजार में वर्षों से बिक रही कुछ दवाओं का कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं था और उनका लगातार उपयोग लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तब चिंता होना स्वाभाविक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध इसी चिंता को उजागर करता है। एफडीसी दवाएं ऐसी औषधियां होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक ही टैबलेट, कैप्सूल या सीरप के रूप में तैयार किया जाता है। कई बार यह व्यवस्था मरीजों के लिए सुविधाजनक और प्रभावी साबित होती है, क्योंकि उन्हें अलग-अलग दवाएं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब विभिन्न दवाओं को बिना पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों और परीक्षणों के मिलाकर बाजार में उतारा जाता है, तब वे लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। सरकार ने जिन 16 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, उनके बारे में विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उनका उपयोग चिकित्सकीय दृष्टि से उचित नहीं था और वे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकती थीं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ये दवाएं इतनी संदिग्ध थीं तो इन्हें बाजार में आने की अनुमति कैसे मिली? यह सवाल केवल उन 16 दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दवा नियामक तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। किसी भी दवा को मंजूरी देने से पहले उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव, सुरक्षा और उपयोगिता की गहन जांच होनी चाहिए। यदि बाद में यह पता चलता है कि दवा का कोई वैज्ञानिक औचित्य ही नहीं था, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं जांच और निगरानी की प्रक्रिया में गंभीर कमी रही है।

और भी चिंताजनक बात यह है कि इन दवाओं की समीक्षा की प्रक्रिया को गति तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश दिए। यह स्थिति दर्शाती है कि कई मामलों में प्रशासनिक और नियामक संस्थाएं सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाती हैं। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह प्रवृत्ति बेहद खतरनाक हो सकती है। यहां एक छोटी सी चूक भी लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां किसी न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर दवाओं की समीक्षा करें और आवश्यक कदम उठाएं। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादकों में से एक है। भारतीय दवाएं दर्जनों देशों में निर्यात की जाती हैं और उनकी सस्ती कीमत तथा उपलब्धता के कारण भारत को विश्व की फार्मेसी तक कहा जाता है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। यदि गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर पड़ता है, तो न केवल देश के नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख पर भी प्रश्न उठने लगते हैं। यही कारण है कि दवा निर्माण के हर चरण में कठोर मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। समय-समय पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी रिपोर्टें भी इस चिंता को बढ़ाती हैं। इन रिपोर्टों में अनेक दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में असफल पाए जाते हैं। कई बार दवाओं में आवश्यक तत्व निर्धारित मात्रा में नहीं मिलते, तो कई बार उनमें ऐसी खामियां पाई जाती हैं जो मरीजों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या केवल कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निगरानी और अनुपालन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।कफ सीरप से जुड़े मामले इस समस्या की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करते हैं। पिछले वर्षों में जहरीले कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हुई थी। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आलोचना हुई थी। बच्चों की मृत्यु जैसी घटनाएं केवल एक कंपनी की लापरवाही नहीं दर्शातीं, बल्कि यह संकेत देती हैं कि निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं बड़ी खामियां मौजूद हैं। यदि निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण और बाजार निगरानी पूरी तरह प्रभावी होती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

युवाओं को जीवटता से जीने की मिले सीख

"शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसे आत्मविश्वासी, संवेदनशील और रचनात्मक नागरिक तैयार करना है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। किसी भी समाज का भविष्य अंततः उन युवाओं पर निर्भर करता है जो संतुलित, मानवीय और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने वाले भी हों।

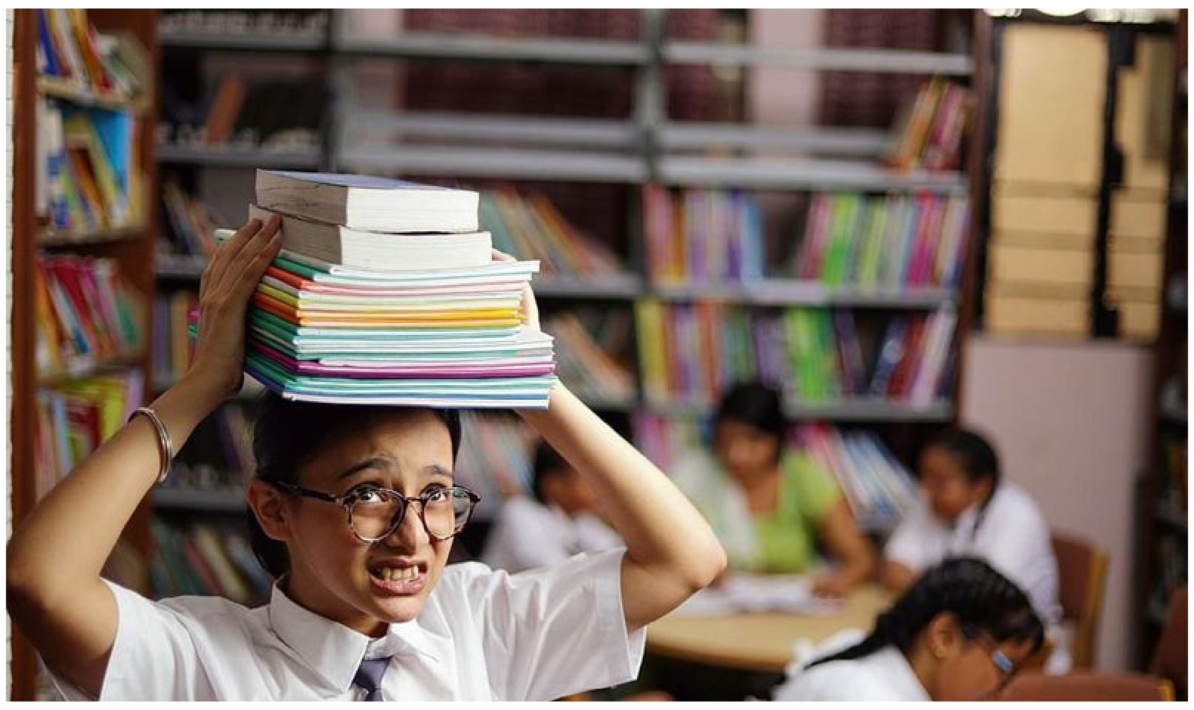

आज देश के लाखों परिवार अपने बच्चों की सफलता के सपने कोचिंग संस्थानों के भरोसे बुन रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनने की आकांक्षा में किशोर उम्र से ही बच्चे ऐसी प्रतिस्पर्धा में उतर जाते हैं, जहां हर परीक्षा भविष्य का फैसला और हर रैंक पहचान का पैमाना बन जाती है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सीमित अवसरों और सामाजिक अपेक्षाओं ने कोचिंग संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। लेकिन इस चमकदार सफलता के पीछे एक दूसरा सच भी छिपा है, जिसमें बढ़ता मानसिक दबाव, सिमटता बचपन और अंकों तक सीमित होती शिक्षा शामिल है। तो क्या हम युवाओं को जीवन के लिए शिक्षित कर रहे हैं या केवल परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं?

भारत दुनिया के सबसे अधिक युवाओं वाले देशों में शामिल है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह स्थिति भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर देती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। हर वर्ष करोड़ों युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्ष 2025 में जेईई मेन परीक्षा में करीब 15 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि आईआईटी में सीटें लगभग 20 हजार हैं। इसी प्रकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों की एक लाख से कम सीटों के लिए लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने नीट यूजी परीक्षा दी। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रतियोगिता अब केवल कठिन नहीं, बल्कि अत्यधिक तीव्र और तनावपूर्ण हो चुकी है।

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारत का कोचिंग उद्योग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद और प्रयागराज जैसे शहर प्रमुख कोचिंग केंद्र बन गए हैं। हजारों विद्यार्थी घरों से दूर रहकर तैयारी करते हैं और अनेक परिवार अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च कर देते हैं। शिक्षा अब ऐसा निवेश बनती जा रही है, जिसके बदले सफलता की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती।

कोचिंग संस्थानों ने अनेक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराया है। छोटे शहरों के कई छात्रों ने इनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। लेकिन इसके साथ डमी एडमिशन जैसी प्रवृत्ति भी बढ़ी है। अनेक विद्यार्थी केवल औपचारिक रूप से स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और उनका अधिकांश समय कोचिंग संस्थानों में बीतता है। इससे खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं।

इस पूरी व्यवस्था का सबसे गंभीर असर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। नियमित टेस्ट, रैंकिंग, प्रदर्शन की तुलना और लगातार बेहतर करने का दबाव बच्चों को मानसिक रूप से थका देता है। असफलता का भय उन्हें चिंता, तनाव और अवसाद की ओर धकेलता है। कई विद्यार्थियों को यह महसूस होने लगता है कि उनका पूरा भविष्य एक परीक्षा के परिणाम पर निर्भर है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। सफलता की यह दौड़ कई बार युवाओं के लिए असहनीय बोझ बन जाती है। हालांकि इस स्थिति के लिए केवल कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभिभावकों और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश माता-पिता बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी अपेक्षाएं अनजाने में दबाव का कारण बन जाती हैं। हमारे समाज में आज भी डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनने को ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के बजाय सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप करियर चुनने के लिए विवश हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि नई अर्थव्यवस्था ने अवसरों के अनेक नए द्वार खोले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मीडिया और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में तेजी से संभावनाएं बढ़ रही हैं। युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

कोचिंग संस्कृति का बढ़ता प्रभाव हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि स्कूल विद्यार्थियों को मजबूत शैक्षणिक आधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और तार्किक समझ प्रदान कर पा रहे होते, तो कोचिंग की आवश्यकता इतनी व्यापक नहीं होती। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, रटने पर आधारित शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा ने इस निर्भरता को बढ़ाया है। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को अधिक कौशल आधारित और बहुआयामी बनाने की दिशा में पहल की है, लेकिन उसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

आज जरूरत शिक्षा व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने में है। स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी करियर परामर्श, विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, अभिभावकों में जागरूकता और सफलता की व्यापक परिभाषा विकसित करना समय की मांग है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसे आत्मविश्वासी, संवेदनशील और रचनात्मक नागरिक तैयार करना है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। किसी भी समाज का भविष्य अंततः उन युवाओं पर निर्भर करता है जो संतुलित, मानवीय और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने वाले भी हों।

प्रेरणा

मधुर शब्दों में छिपा सबसे घातक विष

प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा अपने दरबार में विद्वानों के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे। राजा को विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने और उनके उत्तर जानने में विशेष रुचि थी। एक दिन उन्होंने दरबार में उपस्थित विद्वानों से पूछा, "इस संसार में सबसे तेज काटने वाला और सबसे अधिक विषैला कौन होता है?" प्रश्न सुनते ही दरबार में बैठे विद्वान अपने-अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि ततैया सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका डंक असहनीय पीड़ा देता है। दूसरे विद्वान ने मधुमक्खी का नाम लिया और तीसरे ने बिच्छू को सबसे जहरीला बताया। एक अन्य विद्वान ने कहा कि सांप का विष तो इतना प्रबल होता है कि उसके काटे हुए व्यक्ति को संभलने का अवसर भी नहीं मिलता।

राजा ने सभी उत्तर ध्यान से सुने, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें लगा कि प्रश्न का वास्तविक उत्तर अभी भी सामने नहीं आया है। तब उन्होंने अपने राजगुरु की ओर देखा और विनम्रता से कहा, "गुरुदेव, अब आप ही इस प्रश्न का समाधान कीजिए। आपके अनुभव और ज्ञान से ही मेरी जिज्ञासा शांत हो सकती है।"

राजगुरु कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "राजन, मेरी दृष्टि में संसार में दो ऐसे जीव हैं जिनका विष सबसे अधिक घातक होता है। पहला निंदक और दूसरा चाटुकार।"

दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान आश्चर्य से राजगुरु का मुख देखने लगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, "गुरुदेव, यह कैसे संभव है? निंदक और चाटुकार तो मनुष्य हैं, फिर वे सांप या बिच्छू से अधिक विषैले कैसे हो सकते हैं?"

राजगुरु मुस्कुराए और बोले, "राजन, सांप, बिच्छू या ततैया का विष केवल शरीर को हानि पहुंचाता है। उनका प्रभाव सीमित होता है और समय के साथ उसका उपचार भी संभव है। लेकिन निंदक और चाटुकार का विष मनुष्य के मन, बुद्धि और चरित्र को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि उनका विष सबसे अधिक खतरनाक होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "निंदक के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और कटुता का विष भरा रहता है। वह सामने से मित्रता का दिखावा कर सकता है, लेकिन पीछे से वह ऐसे शब्दों के बाण चलाता है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं। उसकी निंदा धीरे-धीरे समाज में फैलती है और अनेक बार व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। निंदक का उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि अपमान और अवमानना होता है। इसलिए उसका विष मनुष्य को भीतर तक घायल कर देता है।"

इसके बाद राजगुरु ने चाटुकार की चर्चा की। उन्होंने कहा, "लेकिन निंदक से भी अधिक खतरनाक चाटुकार होता है। निंदक का विष कड़वा होता है, इसलिए उसे पहचानना अपेक्षाकृत आसान है। चाटुकार का विष मीठा होता है। वह व्यक्ति की हर बात की प्रशंसा करता है, उसके दोषों को भी गुण बताता है और उसकी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है। धीरे-धीरे वह व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां वह स्वयं को पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है।"

राजगुरु की बात केवल उस युग के लिए नहीं थी, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में चापलूसी एक ऐसी सामाजिक बीमारी बन चुकी है जो राजनीति, प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और यहां तक कि पारिवारिक संबंधों में भी दिखाई देती है। अनेक लोग सत्य बोलने के बजाय केवल प्रसन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि स्वार्थ सिद्धि होता है। वे जानते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वे उसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं।

चापलूसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे-धीरे विवेक को समाप्त कर देती है। जब किसी व्यक्ति को लगातार उसकी प्रशंसा सुनाई जाती है, तो वह अपनी कमियों को देखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह सही है। परिणामस्वरूप आत्ममंथन और आत्मसुधार की प्रक्रिया रुक जाती है। जिस क्षण व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना बंद कर देता है, उसी क्षण उसके विकास की यात्रा भी रुक जाती है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक शक्तिशाली राजा, शासक और नेता चापलूसों के कारण पतन की ओर बढ़े। उनके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो गए जो केवल उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखते थे। जब तक उन्हें सच्चाई का पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। दूसरी ओर वे शासक और नेता अधिक सफल सिद्ध हुए जिन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को स्थान दिया जो निडर होकर सत्य कह सकते थे।

महान संत कबीरदास ने भी इसी सत्य को अपने प्रसिद्ध दोहे में व्यक्त किया है—"निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय।" कबीर का आशय यह नहीं था कि निंदा अच्छी है, बल्कि यह था कि सच्ची आलोचना व्यक्ति को अपनी कमियों का बोध कराती है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है, वह कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। आलोचना यदि सद्भावना और सुधार की भावना से की जाए तो वह दर्पण का कार्य करती है।

आज सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और भी बढ़ गई है। लोग लाइक, प्रशंसा और लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं। अनेक बार व्यक्ति अपने वास्तविक गुणों और क्षमताओं के बजाय दूसरों की वाहवाही पर निर्भर हो जाता है। ऐसे वातावरण में चापलूसी का विष और तेजी से फैलता है। लोग सत्य से अधिक सुखद शब्दों को महत्व देने लगते हैं। परिणामस्वरूप निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति वास्तविकता से दूर होता चला जाता है।

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशंसा और आलोचना दोनों को संतुलित दृष्टि से देखें। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है, वह स्वयं को धोखा देता है। वहीं जो हर आलोचना से घबरा जाता है, वह भी आगे नहीं बढ़ पाता। बुद्धिमानी इसी में है कि हम सत्य को पहचानें, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। सच्चा मित्र वह नहीं जो हर समय हमारी तारीफ करे, बल्कि वह है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी गलतियों की ओर भी संकेत करे।

राजगुरु की बात सुनकर राजा की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार में सबसे घातक विष वह नहीं जो शरीर को मारता है, बल्कि वह है जो मनुष्य के विवेक, विनम्रता और आत्मज्ञान को नष्ट कर देता है। निंदक का विष व्यक्ति को पीड़ा देता है, लेकिन चाटुकार का मीठा विष उसे धीरे-धीरे अहंकार की ऐसी नींद में सुला देता है, जहां से जागना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में मधुर शब्दों से अधिक सत्य शब्दों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाते हैं और वास्तविक उन्नति की ओर ले जाते हैं।

छात्रों के हित में है त्रिभाषा फार्मूला

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं होती, इसका एक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी होता है। खासतौर से जब भाषा का परिप्रेक्ष्य शिक्षा के संदर्भ में हो तो भाषा अपने समाजशास्त्र और आर्थिकी से आगे बढ़कर राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ जाती है। पिछले दिनों देश में सीबीएसई के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने की योजना की घोषणा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह अलग बात है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। यह संतोषजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक नहीं लगाई।

भारत के प्रमुख स्कूली शिक्षा बोर्ड 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' (सीबीएसई) ने हाल में निर्णय लिया कि अकादमिक सत्र 2026-2027 से छठी और नवीं कक्षा से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा है। इसके अनुसार स्कूली स्तर पर तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। पहले भी एनईपी 1968 और एनईपी 1986 आदि में थोड़े से भिन्न रूप में त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया था। एकाध को छोड़कर सभी राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र को लागू किया, लेकिन दुर्भाग्य से सीबीएसई ने त्रिभाषा फार्मूले को आंशिक रूप से ही स्वीकारा था।

सीबीएसई स्कूलों में छठी से आठवीं तक त्रिभाषा सूत्र लागू तो था, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर विदेशी भाषाओं की भी छूट थी, फिर नवीं और दसवीं में तो सीबीएसई ने सिर्फ द्विभाषा नीति ही अपनाई थी। उसमें भी छूट यहां तक कि स्कूल चाहें तो दोनों ही भाषाएं कोई गैर-भारतीय भाषा हो सकती थीं। इसका दुष्परिणाम हुआ कि महंगे पब्लिक स्कूलों में भारतीय भाषाओं को उपेक्षित किया जाने लगा। सीबीएसई की इन नीतियों से कई विसंगतियां पैदा हो गई थीं।

सीबीएसई एवं राज्य बोर्डों के विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण में असंतुलन की स्थिति बन गई थी। वर्तमान योजना का उद्देश्य देशभर में स्कूली शिक्षा में समानता एवं भाषाई एकरूपता स्थापित करना है। दूसरे, नवीं और दसवीं में जब बच्चों का व्यक्तित्व आकार लेना शुरू करता है, उस समय केवल विदेशी भाषाओं तक सीमित रह जाना, बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से दूर करना है। भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का भी संचार करती है। आज बच्चों में त्याग, सेवा, सहिष्णुता, सामूहिकता, परिवार-भाव, बड़ों के प्रति आदर जैसे भारतीय मूल्यों का लोप हो रहा है। एनईपी 2020 का त्रिभाषा सूत्र बच्चों में क्षीण हो रहे इन भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करेगा। सीबीएसई के बच्चों को भी बहुभाषिकता की शक्ति का लाभ मिलेगा।

साइको-लिंग्विस्टिक रिसर्च बताती हैं कि बच्चों में अनेक भाषाएं सीखने की सहज और असीम क्षमता होती है। एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान बच्चों में भारतीय भौगोलिक-सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करेगा। इससे राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूती मिलेगी और विभाजनकारी भाषाई राजनीति कमजोर होगी। भाषा का एक अर्थशास्त्र भी होता है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन से इससे जुड़े प्रकाशन उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लोगों को देशभर में घुलने-मिलने, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में आसानी होगी।

विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही सूचनाएं तथ्यहीन एवं भ्रामक हैं। विरोध का एक कारण अंग्रेजी-शिक्षित आभिजात्य वर्ग की औपनिवेशिक दौर की 'मैकाले मानसिकता' भी है। एक अध्ययन के अनुसार तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई केवल एक प्रतिशत शहरी विद्यार्थी ही कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं के अध्ययन की अनिवार्यता का विरोध इन्हीं के आभिजात्य अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। नए दिशानिर्देशों के विरोध में ये लोग भाषा शिक्षकों की कमी, पाठ्यपुस्तकों का अभाव, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ और तनाव, पहले से विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की असुविधा आदि तर्क दे रहे हैं। ध्यान रहे कि सीबीएसई/एनसीईआरटी द्वारा कक्षा छह के लिए सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें लगभग तैयार हैं।

नवीं कक्षा में त्रिभाषा नीति 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। इसके लिए 19 अनुसूचित भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। अन्य भारतीय भाषाओं के लिए इस वर्ष एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर आनलाइन पद्धति में अन्य स्कूलों से सहयोग कर शिक्षण कार्य असंभव नहीं। केवल एक और भारतीय भाषा की पढ़ाई को अतिरिक्त बोझ बताना, सही समझ का अभाव है। विभिन्न राज्यों में पहले से ही तीन भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। पहले से विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों की सुविधा के लिए वर्तमान में तीसरी भाषा का पाठ्यक्रम हल्का रखा जाएगा। तीसरी भाषा के लिए यह छूट भी है कि दसवीं में इसकी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यही नहीं, कोई छात्र अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी विदेशी भाषा भी सीखना चाहे तो इसका भी अवसर प्राप्त होगा। बड़े सुधारों में प्रारंभ में कुछ चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि त्रिभाषा नीति को सही रूप से लागू करना देश और बच्चों, दोनों के हित में है।

अभियान

आस्था का वह महापर्व, जब भक्त नहीं बल्कि भगवान निकलते हैं यात्रा पर

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में अनेक पर्व ऐसे हैं जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। इनमें पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं, विश्वास और भक्ति का विराट संगम है। विश्वभर में लाखों लोग इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह वह अवसर होता है जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ईश्वर और मानव के बीच प्रेम के अद्वितीय उत्सव के रूप में देखा जाता है।

सामान्य रूप से किसी भी मंदिर में भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। वे लंबी यात्राएं करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और घंटों प्रतीक्षा के बाद अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा इस व्यवस्था को बदल देती है। यहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने का निर्णय लेते हैं। वे अपने भव्य मंदिर से निकलकर विशाल रथों पर विराजमान होते हैं और खुले आकाश के नीचे लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है कि ईश्वर किसी सीमित स्थान या विशेष वर्ग के नहीं होते। वे हर उस व्यक्ति के हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है।

भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भी अन्य देवताओं से भिन्न माना जाता है। वे केवल ओडिशा या भारत के किसी विशेष क्षेत्र के देवता नहीं हैं। 'जगन्नाथ' शब्द का अर्थ ही है—संपूर्ण जगत के स्वामी। यही कारण है कि उनकी पूजा में जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र या किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्थान नहीं दिया गया। रथ यात्रा इस सार्वभौमिक भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भगवान के रथ की रस्सी खींची जाती है, तब वहां राजा और सामान्य नागरिक, धनी और निर्धन, विद्वान और अशिक्षित सभी एक समान होकर खड़े होते हैं। उस समय किसी की सामाजिक पहचान महत्वपूर्ण नहीं होती, केवल उसकी भक्ति और श्रद्धा का महत्व होता है।

रथ की रस्सी खींचने की परंपरा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों और लोकमान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है, उसे विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस सेवा से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हालांकि इस मान्यता का वास्तविक अर्थ केवल कर्मफल से नहीं जुड़ा है। इसका गहरा आध्यात्मिक पक्ष यह है कि रथ की रस्सी पकड़ना अपने जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रतीक है। जब व्यक्ति भगवान के रथ को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, तब वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को पीछे छोड़ने का संकल्प भी लेता है।

रथ यात्रा का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। माना जाता है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। समय बदला, राजवंश बदले, शासन व्यवस्थाएं बदलीं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भव्यता के साथ जारी है। यह तथ्य स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जनमानस की चेतना में गहराई से रचा-बसा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। यह परंपरा अपने आप में अद्भुत है। संसार में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो जहां हर वर्ष इतने विशाल रथों का निर्माण केवल कुछ दिनों की यात्रा के लिए किया जाता हो। भगवान जगन्नाथ के रथ को 'नंदीघोष', बलभद्र के रथ को 'तालध्वज' और देवी सुभद्रा के रथ को 'दर्पदलन' कहा जाता है। इन रथों का निर्माण विशेष प्रकार की लकड़ियों से किया जाता है और निर्माण की पूरी प्रक्रिया धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होती है। कारीगर इसे केवल शिल्पकला का कार्य नहीं, बल्कि भगवान की सेवा मानकर करते हैं।

जब रथ यात्रा का दिन आता है तो पुरी की सड़कों पर आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु केवल एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। जैसे ही भगवान रथ पर विराजमान होते हैं, वातावरण 'जय जगन्नाथ' के उद्घोष से गूंज उठता है। यह दृश्य केवल आंखों से देखने का नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने का होता है। कई भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें लगता है मानो स्वयं भगवान उनके बीच उपस्थित हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।

रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक पक्ष 'छेरा पहरा' की परंपरा है। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के सामने मार्ग को साफ करते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति के उस महान आदर्श को प्रस्तुत करता है जिसमें सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक राजा, जिसके पास अपार वैभव और अधिकार है, वह भी भगवान के सामने स्वयं को सेवक मानता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता अधिकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है।

रथ यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष भगवान का गुंडिचा मंदिर जाना है। लोकमान्यता के अनुसार यह उनकी मौसी का घर है। भगवान अपने भाई और बहन के साथ वहां कुछ दिनों तक निवास करते हैं और फिर पुनः अपने मूल मंदिर लौटते हैं। यह परंपरा भारतीय पारिवारिक मूल्यों का सुंदर प्रतीक है। यह बताती है कि संबंधों में प्रेम, आत्मीयता और अपनापन कितना महत्वपूर्ण है। यहां भगवान भी उसी मानवीय संवेदना का पालन करते दिखाई देते हैं जिसे भारतीय संस्कृति सदियों से महत्व देती आई है।

आध्यात्मिक दृष्टि से रथ यात्रा मानव जीवन की यात्रा का भी प्रतीक मानी जाती है। उपनिषदों में शरीर को रथ, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को यात्री कहा गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान का रथ केवल लकड़ी का बना एक वाहन नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए शक्ति, संतुलन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को भी धर्म, विवेक और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। रथ की रस्सी खींचना इस बात का संकेत है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समावेशी भावना है। यहां किसी को भी भगवान की कृपा से वंचित नहीं माना जाता। जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वह भी रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कर सकता है। यही कारण है कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का भी उत्सव है। यहां हर व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने का समान अधिकार प्राप्त है।

आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार के विभाजनों, संघर्षों और भेदभावों से जूझ रहा है, तब जगन्नाथ रथ यात्रा हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। लाखों लोग एक साथ मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं। वहां न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा। सभी केवल भक्त होते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और सहयोग है।

रथ यात्रा का वास्तविक संदेश केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में विनम्रता, सेवा, समानता और समर्पण का कितना महत्व है। यह बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और निष्काम सेवा से होकर जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्तों तक आने का मार्ग खोज लेते हैं।

इसीलिए हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और भगवान के रथ की रस्सी को छूने का प्रयास करते हैं। उनके लिए वह रस्सी केवल एक मोटी डोरी नहीं होती, बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम होती है। उसे पकड़ते समय वे केवल रथ नहीं खींचते, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ने और ईश्वर के निकट आने का संकल्प लेते हैं।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

इंस्टाग्राम दोस्ती का खौफनाक अंत: सूरत में नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला

सूरत। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मासूम-सी पहचान कैसे धीरे-धीरे अपराध, शोषण और भय के गहरे जाल में बदल सकती है, इसका भयावह उदाहरण गुजरात के सूरत शहर में सामने आया है। यहां एक 18 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लंबे समय तक यौन शोषण किए जाने का गंभीर मामला दर्ज होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि डिजिटल युग में बढ़ते साइबर-मानसिक अपराधों की एक चिंताजनक तस्वीर भी पेश करता है।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, पूरी घटना की शुरुआत इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत से हुई थी, जहां उसकी पहचान आरोपी दीपक से हुई। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन धीरे-धीरे आरोपी ने उसे भरोसे में लेना शुरू किया और दोस्ती को गहरा रिश्ता बताकर मिलने के लिए राजी कर लिया। अगस्त 2025 में दोनों की पहली मुलाकात कतरगाम स्थित एक कॉफी शॉप में हुई, जहां से इस पूरे अपराध की भयावह कहानी शुरू हुई।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उस मुलाकात के दौरान आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ पेय पिलाया, जिसके बाद वह बेहोशी की हालत में चली गई। इसी स्थिति का फायदा उठाकर उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर उसे लगातार ब्लैकमेल करने के लिए किया गया।

शिकायत में यह भी सामने आया है कि इस पूरी घटना के समय आरोपी दीपक का चाचा भी वहां मौजूद था और उसने भी अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई। पीड़िता के अनुसार, जब उसे होश आया तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में थी, लेकिन तब तक आरोपी उसके वीडियो अपने कब्जे में ले चुके थे और उसे धमकाने का सिलसिला शुरू हो चुका था।

इसके बाद पीड़िता को लगातार डर और धमकी के माहौल में रखा गया। आरोपी उसे यह धमकी देता रहा कि यदि उसने किसी को कुछ बताया या विरोध किया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिससे उसका सामाजिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही और मानसिक यातना सहती रही।

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इस ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता का कई बार विभिन्न स्थानों, खासकर होटलों में ले जाकर यौन शोषण

किया। यह शोषण एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और लगातार चलने वाला अपराध बन गया था, जिसमें भय और मानसिक दबाव को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह 18 वर्ष की हुई, तो आरोपी ने उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य यह था कि कानूनी रूप से भी उस पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके और किसी तरह का संदेह या शिकायत न उठे। शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे बाद में राजकोट लेकर गया, जहां उसे अपनी बहन के घर रखा गया और फिर अमरोली स्थित एक होटल में ले जाकर फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि पीड़िता को लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती रही, जिससे वह पूरी तरह मानसिक दबाव में आकर शोषण सहने को मजबूर हो गई।

यह मामला इस बात को उजागर करता है कि किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनी पहचानें वास्तविक जीवन में गंभीर अपराधों का रूप ले सकती हैं।

मामला सामने आने के बाद सिंगनपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीपक, उसके चाचा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल डेटा, लोकेशन ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहन जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह भी जांच का विषय है कि क्या आरोपी किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो इस तरह के अपराधों में शामिल हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर युवाओं की बढ़ती असुरक्षा और ऑनलाइन दोस्ती के खतरों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि डिजिटल जागरूकता और पारिवारिक सतर्कता भी बेहद जरूरी है।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया है कि क्या डिजिटल युग में भरोसे की कीमत इतनी भारी हो सकती है कि एक सामान्य दोस्ती जीवनभर की मानसिक और सामाजिक पीड़ा में बदल जाए। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश की जा रही है।

काशी में रेलवे नोटिस से विवाद गहराया, गंज शहीदा मस्जिद मामला पहुंचा राजनीतिक और कूटनीतिक बहस तक

वाराणसी। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नोटिस ने स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार के पास रेलवे भूमि पर स्थित गंज शहीदा मस्जिद को हटाने के लिए जारी नोटिस के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की सोशल मीडिया टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई।

रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि काशी स्टेशन के विस्तार और पुनर्विकास कार्यों के लिए यह भूमि आवश्यक है और वहां मौजूद संरचना निर्माण कार्य में बाधा बन रही है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि संबंधित स्थल रेलवे की भूमि है, जिस पर बिना अनुमति निर्माण किया गया था। इसी आधार पर मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर संरचना हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं मस्जिद प्रबंधन समिति ने रेलवे के दावों को सिरे से खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि नोटिस में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और जिस भूमि विवाद या मुकदमे का उल्लेख किया गया है, उसका मस्जिद से सीधा संबंध नहीं है। समिति ने दावा किया है कि गंज शहीदा मस्जिद वर्षों पुरानी धार्मिक संरचना है और यह रेलवे के अस्तित्व में आने से भी पहले से वहां मौजूद है। ऐसे में इसे अवैध निर्माण कहना गलत है और यह ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी है।

मस्जिद प्रबंधन ने यह भी कहा है कि वे इस मामले में कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का कहना है कि यह विवाद केवल भूमि उपयोग का मामला है, जिसे संवाद और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। इस बीच मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद सहित कुछ ऐतिहासिक मुस्लिम स्थलों का उल्लेख किया और उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनकी इस टिप्पणी के बाद भारत में राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

वाराणसी प्रशासन और कई स्थानीय धार्मिक नेताओं ने विदेशी हस्तक्षेप पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह भारत का आंतरिक प्रशासनिक और कानूनी मामला है, और इसमें किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की टिप्पणी उचित नहीं मानी जा सकती। उनका कहना है कि ऐसे मामलों का समाधान भारतीय कानून और न्यायिक व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास कार्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और भीड़भाड़ को कम करना है। इसी क्रम में आसपास के अतिक्रमण और संरचनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और उचित नोटिस के बाद ही की जा रही है।

दूसरी ओर, स्थानीय स्तर पर कुछ सामाजिक संगठनों ने अपील की है कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बचा जाए और दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। उनका कहना है कि काशी जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोपरि है।

फिलहाल यह मामला प्रशासनिक प्रक्रिया, कानूनी दावों और राजनीतिक बयानों के बीच उलझा हुआ है। सभी की नजर अब आगे होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है, जिससे यह तय होगा कि इस विवाद का अंतिम समाधान किस दिशा में जाता है।

बुंदेलखंड को बदनाम करने वालों का समय खत्म, अब विकास और निवेश का नया युग: योगी आदित्यनाथ

महोबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महोबा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक बुंदेलखंड की छवि को नकारात्मकता और पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब विकास, निवेश और आत्मनिर्भरता के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार उसे धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने महोबा में 697 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा कर जनता तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज बुंदेलखंड में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने योग के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं ताकि स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। योग दिवस के अवसर पर उन्होंने जनसामान्य को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र वीरता, पराक्रम और संघर्ष की भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से लंबे समय तक इस क्षेत्र को पिछड़ेपन, सूखे और पलायन के लिए जाना गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से यहां के विकास की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि अब बुंदेलखंड केवल अतीत की समस्याओं का प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का केंद्र बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से केन-बेतवा लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके पूरा होने के बाद बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने हर घर जल योजना और अन्य जल संरक्षण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने गोरखगिरि पर्वत को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यहां रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब केवल कृषि या पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यहां रक्षा उत्पादन, औद्योगिक इकाइयों और निवेश के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में यह इलाका औद्योगिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

वर्ल्ड में पहली बार चलती ट्रेन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,डीआरएम वेद प्रकाश ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के साथ किया योगाभ्यास

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर 21 जून 2026 को मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के कुशल मार्गदर्शन में 12वाँ 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न प्रमुख स्थलों के साथ-साथ चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। भारतीय रेलवे में पहली बार चलती ट्रेनों में यात्रियों को योग से जोड़ने की यह अभिनव पहल अहमदाबाद मंडल द्वारा की गई।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद मंडल द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। सबसे पहले हमने अपने सभी कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को योग से जोड़ने का प्रयास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से हमारे विभिन्न केंद्रों तथा रेलवे संस्थानों में बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया।

दूसरी विशेष पहल के रूप में आज हमने वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को योग से जोड़ने की एक अनूठी पहल की है। इस अभियान के तहत ट्रेनों के 'पाइप्ड म्यूजिक' (ऑडियो सिस्टम) के माध्यम से योग गुरुओं के निर्देश प्रसारित किए गए तथा प्रत्येक कोच में उपस्थित वॉलंटियर्स ने यात्रियों को अपनी सीट पर बैठे-बैठे 'सूक्ष्म योग' करने में सहयोग प्रदान किया। यात्रियों ने 10 से 20 मिनट तक गर्दन, हाथ, कलाई एवं कंधों के रोटेशन, ओम् के उच्चारण तथा ध्यान जैसे सरल योगाभ्यास किए। योग मन, वचन, कर्म और काया के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ एक स्वस्थ समाज, सशक्त राष्ट्र और बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग हमें संतुलन, अनुशासन और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सामुदायिक भवन, साबरमती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में योगगुरु श्री अल्पेश त्रिवेदी एवं श्रीमती हंषा चाग ने रेल अधिकारियों, कर्मचारियों, आरपीएफ स्टाफ, स्काउट एवं गाइड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन (सिविल डिफेंस) के सदस्यों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न आसनों, प्राणायाम एवं ध्यान संबंधी अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त ओल्ड रेलवे इंस्टीट्यूट-साबरमती, रेलवे इंस्टीट्यूट-कांकरिया, सामुदायिक भवन-गांधीधाम तथा सामुदायिक भवन-वीरमगाम में भी योग सत्र आयोजित किए गए।

चलती वंदे भारत ट्रेनों में विशेष योग सत्रइस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को और अधिक जनसुलभ एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें यात्रियों ने सीट पर बैठकर किए जाने वाले सरल योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास किया—

1. गाड़ी संख्या 20902 गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस
2. गाड़ी संख्या 12462 साबरमती – जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
3. गाड़ी संख्या 26964 असारवा – उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. गाड़ी संख्या 22925 अहमदाबाद – ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस

अहमदाबाद मंडल द्वारा पूर्व में भी अहमदाबाद, महेसाणा, पालनपुर तथा गांधीधाम सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर योग शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनमें रेल कर्मचारियों एवं यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम "Yoga for Healthy Ageing" के अनुरूप पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल स्वस्थ जीवनशैली और सामूहिक कल्याण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे अपने सभी सम्मानित रेल यात्रियों एवं रेल कर्मियों से अपील करता है कि वे योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ें तथा इस वैश्विक अभियान से जुड़ें।

शेयर बाजार की चमक से बढ़ी दिग्गजों की दौलत, एक सप्ताह में टॉप कंपनियों ने जोड़े 2.15 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी ने देश की दिग्गज कंपनियों को जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान निवेशकों की सकारात्मक धारणा, मजबूत खरीदारी और बाजार में लौटे उत्साह का सीधा असर देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों पर देखने को मिला। शीर्ष 10 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कुल 2.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी ने न केवल कंपनियों के मूल्यांकन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं में कुछ कमी, विदेशी निवेशकों की वापसी, घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और कॉरपोरेट क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने बाजार को नई ऊर्जा प्रदान की है। इसी सकारात्मक माहौल का लाभ सबसे अधिक देश की बड़ी कंपनियों को मिला, जिनके शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली।

सप्ताह का सबसे बड़ा लाभार्थी दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Bharti Airtel रही। कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 52,432 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई, जिसके बाद उसका कुल मूल्यांकन 11.62 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। दूरसंचार क्षेत्र में लगातार बढ़ते ग्राहक आधार, डेटा सेवाओं की मांग और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। यही कारण है कि कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई।

बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी Life Insurance Corporation of India ने भी बाजार में शानदार प्रदर्शन किया। एलआईसी के बाजार पूंजीकरण में 51,675 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और कंपनी का कुल मूल्यांकन 5.56 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। हाल के महीनों में एलआईसी के शेयरों में आई मजबूती ने यह संकेत दिया है कि निवेशक सार्वजनिक क्षेत्र की इस दिग्गज बीमा कंपनी को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

वित्तीय सेवा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी Bajaj Finance के बाजार मूल्य में भी उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया। उपभोक्ता ऋण, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और मजबूत कारोबारी विस्तार के कारण कंपनी लगातार निवेशकों की पसंद बनी हुई है। इसी प्रकार देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी Reliance Industries ने भी अपने मूल्यांकन में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा कारोबार और नई तकनीकों में निवेश के कारण रिलायंस लगातार बाजार की प्रमुख कंपनियों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।

इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी Larsen & Toubro के बाजार पूंजीकरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। देशभर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विस्तार और सरकारी निवेश योजनाओं का लाभ कंपनी को मिल रहा है, जिससे उसके शेयरों में मजबूती बनी हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं State Bank of India, HDFC Bank और ICICI Bank के बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। इन बैंकों के मजबूत वित्तीय परिणाम, ऋण वितरण में वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। इसके अलावा उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Hindustan Unilever ने भी बाजार पूंजीकरण में वृद्धि दर्ज की।

हालांकि इस व्यापक तेजी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Tata Consultancy Services को नुकसान का सामना करना पड़ा। सप्ताह के दौरान कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 12,699 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक आईटी खर्च में संभावित नरमी और विदेशी बाजारों में मांग को लेकर बनी चिंताओं का असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया। हालांकि इसके बावजूद टीसीएस देश की सबसे मजबूत और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में शामिल बनी हुई है।

यदि कुल बाजार मूल्यांकन की बात करें तो Reliance Industries अब भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 17.71 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद HDFC Bank, Bharti Airtel, ICICI Bank और State Bank of India का स्थान है। इन कंपनियों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मजबूती और निवेशकों का विश्वास मौजूद है।

विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन केवल कंपनियों की कमाई का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा, निवेश माहौल और भविष्य की संभावनाओं का भी संकेतक होता है। पिछले कुछ समय से विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी, घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और आर्थिक गतिविधियों में निरंतर सुधार ने बाजार को मजबूती प्रदान की है।

वडोदरा स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग प्रगति पर एकतानगर की कुछ वीकली ट्रेनें होगी डाइवर्टेड, कुछ ट्रेनों का वडोदरा की जगह विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों पर हॉल्ट

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा स्टेशन पर व्यापक यार्ड रीमॉडलिंग एवं ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में प्लेटफार्म नंबर 5 एवं 6 की रेल लाइन पर पॉइंट एवं क्रॉसओवर को बैठाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे इन प्लेटफार्म पर 23 जून से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। यात्रियों को न्यूनतम असुविधा को ध्यान में रखते तथा इंफ्रा के इस कार्य की जारी रखते हुए एकतानगर की कुछ वीकली ट्रेनें वडोदरा आने की बजाय डाइवर्टेड रुट डभोई - मियागाम कर्जन पर परिचालित होंगी। कुछ ट्रेनों को वडोदरा के स्थान पर शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़े विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों

पर हॉल्ट दिया जायेगा। वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य परिचालन संरक्षा में वृद्धि, लाइन एवं प्लेटफॉर्म क्षमता का विस्तार, ट्रेन संचालन दक्षता में सुधार तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। 23 जून से 1 जुलाई ,2026 तक डाइवर्ट रुट डभोई - मियागाम कर्जन पर चलने वाली एवं विश्वामित्री, छायापुरी एवं बाजवा स्टेशनों पर हॉल्ट शिफ्ट होने वाली ट्रेनें निम्न है :

ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क भारत, पश्चिम एशिया तनाव के बीच रूस और यूएई से बढ़ाई तेल खरीद

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में समय-समय पर उभरने वाले भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियों ने रूस और संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह रणनीति केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी भी आपूर्ति संकट से देश को सुरक्षित रखने की व्यापक योजना का हिस्सा मानी जा रही है।

भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले किसी भी उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार और तेल कंपनियां लगातार ऐसे विकल्पों की तलाश में रहती हैं, जिनसे ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और किसी एक क्षेत्र या मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।

समुद्री और कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म कपलर के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 19 जून तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, जबकि मई महीने में यह आंकड़ा 19.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय कंपनियां रूस को अपने सबसे भरोसेमंद और लाभकारी आपूर्तिकर्ताओं में से एक मान रही हैं।

रूस पिछले कुछ वर्षों से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और वैश्विक बाजार में आई उथल-पुथल के बीच रूस ने अपने तेल को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। इसका लाभ भारतीय रिफाइनरियों ने बड़े पैमाने पर उठाया। कम कीमत पर उपलब्ध रूसी तेल ने न केवल भारतीय कंपनियों की लागत कम की, बल्कि घरेलू बाजार में ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रूस के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात से भी भारत ने अपनी तेल खरीद बढ़ाई है। जून में यूएई से औसतन 6.36 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई से बढ़ी हुई खरीद भारत की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे खाड़ी क्षेत्र के साथ आपूर्ति संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यूएई लंबे समय से भारत का एक भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं।

इस बीच वैश्विक तेल व्यापार में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है। वेनेजुएला भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। यह संकेत देता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों पर ध्यान दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका से तेल आयात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जून में अमेरिका से आयात घटकर मात्र 91 हजार बैरल प्रतिदिन रह गया। विशेषज्ञों का मानना है कि मूल्य, परिवहन लागत और आपूर्ति की व्यावसायिक शर्तों के कारण भारतीय कंपनियां फिलहाल रूस और कुछ अन्य देशों को प्राथमिकता दे रही हैं।

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में हॉर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकीर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार की जीवनरेखा माना जाता है। दुनिया की कुल समुद्री तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों के लिए यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारण से इस जलडमरूमध्य में बाधा उत्पन्न होती है तो वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आ सकता है और अनेक देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

हाल के महीनों में ईरान और क्षेत्रीय तनावों को लेकर उत्पन्न चिंताओं ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सतर्क कर दिया था। कई विश्लेषकों ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हालांकि बाद में युद्धविराम और कूटनीतिक प्रयासों के कारण तनाव में कमी आई, जिससे बाजारों को राहत मिली।

युद्धविराम के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से तेल और गैस वाहक जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है।

12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति में गांधीनगर के माणसा में 12वें विश्व योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव भव्य रूप से मनाया गया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- 12वें विश्व योग दिवस और प्रधानमंत्री के सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने का शुभ समन्वय
- प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का महत्वपूर्ण माध्यम बना
- योग क्षेत्र में गुजरात देश में अग्रणी : 1.5 लाख प्रशिक्षक, पाँच हजार योग केन्द्रों के माध्यम से एक वर्ष में 8 लाख लोग योग से जुड़े
- राजकोट बनेगा देश की अनूठी '15 मिनट योग सिटी'

- **योग को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनाकर 'विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करें : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
- **योग को केवल एक दिवस के कार्यक्रम तक सीमित न रखकर दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का मुख्यमंत्री का आह्वान**
- **समग्र राज्य में एक साथ 330 स्थानों पर सवा करोड़ से अधिक बच्चों, युवाओं तथा बड़े-बुजुर्गों ने योगाभ्यास किया**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति में गांधीनगर के माणसा में रविवार को 12वें विश्व योग दिवस का राज्य स्तरीय उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहकर हमारी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए।

इसके साथ ही पूरे राज्य में एक साथ लगभग सवा करोड़ से अधिक बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने विभिन्न स्थानों से इस उत्सव में जुड़कर योगाभ्यास किया।

राज्य के सभी नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से हमारी सनातन प्राचीन योग संस्कृति को आज विश्वभर में स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि 12वें विश्व योग दिवस का उत्सव इस दृष्टि से भी विशेष है कि प्रधानमंत्री के सुशासन के भी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 'फिट इंडिया' तथा 'विश्व योग दिवस' जैसी बड़ी भेंट दी है, जिसके परिणामस्वरूप योग आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसके साथ ही पर्यावरण

संरक्षण के लिए 'एक पेड़ माँ के नाम', 'कैच द रेन' तथा सोलर एनर्जी द्वारा ग्रीन-क्लीन ऊर्जा का दृष्टिकोण और रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती तथा 'मिशन लाइफ' द्वारा पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी प्रधानमंत्री ने दिखाया है।

मुख्यमंत्री ने बलपूर्वक कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों के विरुद्ध योग स्वास्थ्यप्रद जीवन का सबसे सरल एवं सटीक मार्ग है।

श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' है। 12वें विश्व योग दिवस पर समग्र गुजरात में विभिन्न स्थानों पर 330 से अधिक स्थानों पर सवा करोड़ से भी अधिक लोग सामूहिक योग में जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने गौरवपूर्वक कहा कि गुजरात योग क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहा है। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 1.5 लाख योग प्रशिक्षक तैयार कर देश में सर्वाधिक प्रशिक्षक तैयार करने की उपलब्धि प्राप्त की गई है। राज्य में 5000 से अधिक निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से एक वर्ष में 8 लाख से अधिक लोगों को योग से जोड़ा गया है।

इतना ही नहीं; राजकोट महानगर पालिका ने योग बोर्ड के साथ विशेष एमओयू कर '15 मिनट योग सिटी' का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शहर के किसी भी स्थान से 15 मिनट की दूरी पर योग केन्द्र उपलब्ध हो; ऐसी व्यवस्था करने का आयोजन है।

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ योग को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनाकर सभी लोग 'विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047' के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के कार्य में जुड़ जाएँ।

राज्य योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री शीशपाल राजपूत ने सभी का स्वागत करते हुए दैनिक जीवन में योग का महत्व समझाया। उन्होंने योग को सनातन ऋषि परंपरा की अद्वितीय भेंट बताते हुए 365 दिनों तक योग को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल के साथ सभी को योगाभ्यास भी कराया।

इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

इस कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश पटेल, विधायक श्री जयंतीभाई पटेल व श्री प्रकाशभाई वरमोरा, माणसा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सनाबेन वाघेला, तहसील पंचायत अध्यक्ष श्री भरतसिंह राठौड़, सर्वोदय एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. वी. एन. शाह, जिला कलेक्टर श्री रवीन्द्र खताले तथा जिला विकास अधिकारी सुश्री हसरत जैस्मीन सहित बड़ी संख्या में योग कोच, योग प्रशिक्षक और योगकर्मी उपस्थित रहे।

2020-26 में मोदी के चुनाव प्रचार पर 2586 करोड़ खर्च हुए: क्या इससे मीडिया पर सरकार का प्रभाव बढ़ा?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

देश में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त एक जवाब से पता चला है कि केंद्र सरकार ने 2020 से 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के विज्ञापनों पर लगभग 2586 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इस परियोजना पर कुल करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। 25,86,00,00,000 रुपये। और यह खर्च भारतीय करदाताओं के पैसे से किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने यह जानकारी देते हुए आरटीआई दाखिल की है।

गोखले ने 1 जून को एक आरटीआई आवेदन दायर कर मोदी के चुनाव अभियान के लिए केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंट और होर्डिंग्स सहित सभी प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का खुलासा करने की मांग की थी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 16 जून को आंकड़े जारी किए। इनमें 2020 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुसार व्यय का उल्लेख किया गया है। गोखले ने कहा कि हालांकि, जिन एजेंसियों को यह राशि प्राप्त हुई है, उनके नाम गुप्त रखे गए हैं। यह भारी आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि अकेले प्रिंट मीडिया में ही पार्टी ने 2025-26 में लगभग 338 करोड़ रुपये खर्च किए। जारी आंकड़ों के अनुसार, यह राशि पिछले वर्ष के 8316 करोड़ रुपये के व्यय से चार गुना अधिक है। कुल मिलाकर, 2020 से 2026 के बीच प्रिंट विज्ञापन पर व्यय 796 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।

गोखले ने दावा किया कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकारी विज्ञापनों के जरिए मीडिया को नियंत्रित करते हैं। तो, जब मोदी और भाजपा के प्रचार पर 2586 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य होता है कि हमारे मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है?

लगातार 5 साल तक खड़े रहना? दुलालगिरी महाराज के घोर तपस्या के दावे का वीडियो वायरल हो रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

दुललगिरी महाराज के नाम से जाने जाने वाले एक भिक्षु की कुछ तस्वीरें और वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि यह महाराज शिव की अत्यंत कठिन ध्यान साधना कर रहे हैं और उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है।

सामान्यतया तपस्या और ध्यान बैठकर किया जाता है, लेकिन इस महाराज ने खड़े होकर तपस्या की है। वीडियो में दावा किया गया है कि यह महाराज कम से कम पांच वर्षों से खड़े हैं। वे खड़े-खड़े ही विश्राम करते हैं। इसीलिए उन्हें झूले पर अपने शरीर का अगला हिस्सा टिकाकर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है।

लगातार खड़े रहने के कारण उनके घुटने सूज गए हैं। पैरों में रक्त संचार रुकने के कारण उनके पैर नीचे से काले पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि दुलालगिरी महाराज पांच साल नहीं बल्कि बारह साल से यह तपस्या कर रहे हैं। हालांकि, इन दावों की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भावनगर रेलवे मंडल के मंडल कार्यालय एवं विभिन्न स्टेशनों पर योगाभ्यास का आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 21 जून, 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मंडल मुख्यालय सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रातः 06:00 बजे सामूहिक योग सत्रों का आयोजन किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "योगा फॉर हेल्दी एजिंग" (Yoga for Healthy Ageing) अर्थात "स्वस्थ आयु के लिए योग" निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

मंडल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति, भावनगर के योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा

श्रीमती शालिनी वर्मा तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के साथ मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान संबंधी अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ताड़ासन, वज्रासन, पवनमुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम-विलोम तथा ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी को नियमित योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश देते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वेलफेयर टीम द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों जैसे भावनगर टर्मिनस, बोटाद, वेरावल, पोरबंदर, जूनागढ़, सिहोर, भाणवड, अमरेली, ढसा, लाठी, जेतलसर एवं गांधीग्राम सहित अन्य स्टेशनों पर भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें रेलवे कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

हाल में जेल केवल सजा भुगतने का स्थान नहीं, बल्कि एक 'प्रायश्चित भवन' और सुधार गृह है : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल

गुजरात की जेल व्यवस्था को मिलेगी नई शक्ति : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल के करकमलों से गांधीनगर से वर्ग-1 तथा 2 के कुल 11 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए

गांधीनगर : जेल प्रभाग के राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल ने कहा है कि वर्तमान समय में जेल केवल सजा भुगतने का स्थान नहीं है, बल्कि एक 'प्रायश्चित भवन' और सुधार गृह बन चुकी है। जब हम पूरी ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तब ईश्वर हमारे परिवार की भी चिंता करता है।

श्री पटेल ने गृह विभाग के जेल प्रभाग के अंतर्गत नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले वर्ग-1 और वर्ग-2 के कुल 11 अधिकारियों को रविवार को गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल में नियुक्ति पत्र प्रदान समारोह में यह बात कही। कार्यक्रम में श्री पटेल तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर श्री पटेल ने भगवान श्री कृष्ण के 'कर्मयोग के सिद्धांत' को स्मरण करते हुए नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों को निष्ठापूर्वक एवं उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जेल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात

अपराधी या आपराधिक मानसिकता वाला नहीं होता। कई बार अपराधी परिस्थितिवश भी अपराध की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें मानवता तथा निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सरकार पर्याप्त आयोजना कर रही है, लेकिन जेल में आने वाले कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहना भी बहुत अनिवार्य है। कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जेल अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वयं मानसिक रूप से पावरफुल और मजबूत बनना होगा। साबरमती जेल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ कैदियों द्वारा बढ़ई कार्य, फर्नीचर निर्माण और फूड पैकिंग जैसे अनेक छोटे-बड़े उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण से कैदी जेल से बाहर जाकर भी आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त; जेल में रहने वाली महिलाओं और यदि उनके साथ कोई मासूम बच्चा हो, तो उनके प्रति विशेष मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जेल प्रशासन को अधिक सशक्त, आधुनिक और कार्यक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि नई नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों के जुड़ने से जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक सेवाओं को अधिक गति मिलेगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि गुजरात में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो, वहाँ जेल सुधार के ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें कि पूरे देश में गुजरात की जेलों और हमारे विभाग का संज्ञान लिए जाने के साथ गौरव बढ़े।

इस अवसर पर प्रधान सचिव (गृह) श्रीमती निपुणा तोरवणे, गृह विभाग एवं जेल प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा नई नियुक्ति प्राप्त अधिकारी उपस्थित रहे।

नियुक्ति प्राप्त अधिकारी

अधीक्षक, केन्द्रीय जेल / पोरबंदर विशेष जेल, वर्ग-1

1.श्री अतुलकुमार छगनभाई मकवाणा
2.सुश्री डिम्पल अर्जुनभाई पटेल
3.श्री गौतमकुमार हरेशभाई व्यास
4.श्री सौरभकुमार लक्ष्मणभाई राठौड़
5.श्री शैलेषकुमार रमणलाल सागर

जेलर ग्रुप-1 (पुरुष), वर्ग-2

1.श्री परेशभाई वशरामभाई डांगर
2.श्री अनीश हसन सुमरा
3.श्री डाह्याभाई मोडाभाई डीघारी
4.श्री सागरकुमार ओघडभाई कलसरिया
5.श्री आर्यन करशनभाई पटेल
6.श्री मेहुलभाई चीकाभाई धरजिया

वडोदरा मंडल पर 12वें अंतरष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह पूर्वक आयोजन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 12वाँ "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वडोदरा मंडल पर "स्वस्थ आयु के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing)" की थीम पर योग सत्र का आयोजन किया गया । प्रतापनगर स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में प्रातः 6:00 बजे से 7:50 बजे तक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ हुआ।

वडोदरा शहर की जानीमानी योग गुरु श्रीमती कृष्णा पटेल एवं कुमारी ख़ुशी पटेल तथा उनकी टीम के मार्गदर्शन में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान संबंधी सुन्दर योगाभ्यास किया।

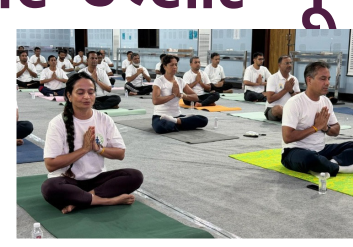

इस अवसर पर वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने अपने संबोधन में कहा कि योग हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की इस अनमोल प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना जरूरी है । योग हमें स्ट्रेस और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी व तनावमुक्त जीवन की ओर ले जाता है और जीवन में नई संभावनाएं व ऊर्जा उत्पन्न करता है। "योग को न केवल रेल कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए अपितु अपने परिजनों को भी इस हेतु प्रेरित करना चाहिए ताकि सभी लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें"।

सामूहिक योग अभ्यास के इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संगठन की अन्य सदस्याएं, रेलवे सुरक्षा बल, तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी, अधिकारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार एवं उनकी वेलफेयर टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

गांधीनगर में आगामी 23 जून को 'गुजरात टू ग्लोबल : एम्पावरिंग द मेडटेक इकोसिस्टम' परिषद का किया जाएगा आयोजन

मेडटेक क्षेत्र में गुजरात की वैश्विक उड़ान को गति देगी यह ग्रिट तथा ईपीसीएमडी इंडिया परिषद

गांधीनगर : गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस (ईपीसीएमडी इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से 'गुजरात टू ग्लोबल : एम्पावरिंग द मेडटेक इकोसिस्टम' शीर्षक अंतर्गत मेडटेक क्षेत्र की एक उच्चस्तरीय परिषद का आयोजन आगामी 23 जून, 2026, मंगलवार को गांधीनगर में किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन क्षमताओं एवं वैश्विक बाजारों में प्रवेश के बीच अंतर को दूर करना है। इसके लिए नीति निर्माताओं, नियमनकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा उद्योग जगत के अग्रणियों को एक ही मंच पर लाया जाएगा।

यह कार्यक्रम गुजरात के मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में आयोजित हो रहा है। राजकोट के निकट स्थित नागलपर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यरत होने से राज्य के उत्पादक अब मूलभूत असेंबली से आगे बढ़कर उच्च गुणवत्ता वाले तथा निर्यातोन्मुख उत्पादों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इस समग्र कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रिट की सीईओ श्रीमती एस. अपर्णा द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग तथा वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त; उद्योग एवं सरकार के दो दर्जन से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में सक्रिय भाग लेंगे।

दिनभर की चर्चाओं की शुरुआत नीति एवं उद्योग संबंधी मुद्दों पर आधारित सत्र से होगी। इसमें '2030 रोडमैप : देश के 30 अरब डॉलर के मेडटेक विजन में गुजरात की भूमिका' संबंधी प्रस्तुति द्वारा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद गुजरात के उत्पादकों के दृष्टिकोण से नीति, नियमनकारी ढाँचे और बाजार तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों पर संवाद-चर्चा आयोजित होगी। फार्मास्युटिकल्स विभाग, वाणिज्य विभाग और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा; एसएमटी, बीपीएल, मेरिल लाइफ साइंस और फिलिप्स इंडिया जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे।

यहाँ विशेष तकनीकी सत्र में वैश्विक नियमनकारी मंजूरियों के लिए निर्णायक ढाँचा प्रस्तुत किया जाएगा; जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के विभिन्न मार्गों (510(k), De Novo, PMA) तथा EU MDR और IVDR की आवश्यकताओं के साथ उनकी सुसंगतता पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में सीडीएससीओ, एफडीए के थर्ड-पार्टी समीक्षा संस्थानों और यूरोपीय नोटिफाइड बॉडीज के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।

इसके बाद के सत्र में वैश्विक बाजारों में प्रवेश के लिए निर्यातोन्मुख गुणवत्ता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसमें जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट (ZED) मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों के साथ जोड़ने तथा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है; इस विषय पर चर्चा होगी। इस सत्र में Invest India, ADMI, Panacea Medical Technologies तथा Wipro GE Healthcare सहित विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

अंतिम सत्र गुजरात के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए सहायक इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित रहेगा। इसमें आधारभूत सुविधाएँ, नियमनकारी सहायता, अनुसंधान एवं नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण, कौशल विकास तथा उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रिट राज्य का सर्वोच्च नीति विचार मंच है, जो शासन सुधार एवं विकासोन्मुख रणनीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि ईपीसीएमडी इंडिया भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग के अधीन कार्यरत संस्थान है, जिसे भारतीय मेडिकल डिवाइसेस के वैश्विक स्तर पर निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी निभानी होती है।

पश्चिम रेलवे पर उत्साहपूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,स्वस्थ आयु के लिए योग : समग्र स्वास्थ्य एवं सक्रिय जीवनशैली के महत्व पर दिया गया विशेष जोर

पश्चिम रेलवे पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रविवार, 21 जून, 2026 को पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखी गई थी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण से हुई, जिसके पश्चात राष्ट्रव्यापी कॉमन योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके उपरांत पश्चिम रेलवे मुख्यालय में एक योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय, प्रमुख विभागाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों, मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों

तथा रेल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

"स्वस्थ आयु के लिए योग" विषय जीवनभर शारीरिक गतिशीलता, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र स्फूर्ति को बढ़ावा देने में योग के महत्व को रेखांकित करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, माइंडफुल ब्रीदिंग तथा आंतरिक संतुलन पर बल देने के माध्यम से योग स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर पश्चिम रेलवे अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के बीच समग्र स्वास्थ्य तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को निरंतर बढ़ावा दे रही है।

प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान अभ्यासों का प्रदर्शन किया तथा शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता एवं समग्र स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों, कारखानों, प्रशिक्षण संस्थानों, डिपो, शेडों तथा अन्य रेल प्रतिष्ठानों में भी योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली, जो योग के लाभों तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से जागरूकता संदेश एवं डिजिटल क्रिएटिव भी प्रसारित किए। इन पहलों के माध्यम से पश्चिम रेलवे ने अपने कर्मचारियों एवं यात्रियों के बीच स्वास्थ्य, कल्याण एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।